

Survey of the Raw Material in Backward District of Hoshiarpur, Punjab

1983. CHOWDHURY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether survey of the raw material available in Hoshiarpur District of Punjab which is a backward district has been made in order to find out the type of industries that could be set up in that district;

(b) if so, the type of industries proposed to be set up and the places selected for that purpose; and

(c) the financial and other help/assistance proposed to be given by Government to the parties who propose to set up industry in that district?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The State Govt. gives assistance/subsidy in respect of land, use of power, taxes etc. The district is covered under the Central Capital Subsidy Scheme and Concessional Finance. As the district is covered by Rural Industries Project which is a Centrally sponsored scheme, Govt. of India makes also budgetary provision for giving loan at concessional interest rate to units set up in the project area.

स्टाकिस्टों द्वारा सीमेंट के अधिक मूल्य वसूल किया जाना

1984. श्री रामलाल राही : क्या उद्योग मंत्री 27 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 4982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1976 में उपभोक्ताओं को किस दर पर सीमेंट दिये जाने के निर्देश

थे तथा क्या स्टाकिस्टों ने जनवरी, 1977 के अंतिम सप्ताह तथा फरवरी, 1977 में सीमेंट के दाम बढ़ा कर वसूल किये और यदि हां, तो दोनों दरों में क्या अंतर था; और

(ख) क्या सीमेंट के फुटकर दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं; और यदि हां, तो यह मूल्य वृद्धि रोकने के लिये क्या कायबाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :

(क) और (ख) समय समय पर यथा संशोधित सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त एक समान मूल्य निर्धारित किया जाता है ; जबकि सीमेंट का थोक अथवा खुदरा विक्रय मूल्य (1) केन्द्र सरकार द्वारा रेलभाड़ा मुक्त गन्तव्य स्थान तक निर्धारित मूल्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा ; (2) लादने उतारने (पैकिंग और कन्टेनरों के प्रभार सहित) और लाने ले जाने के प्रभार ; (3) गोदाम प्रभार ; (4) स्टाकिस्टों के लाभ की सीमा ; (5) स्थानीय कर, यदि कोई हों ; और (6) अनुमत अतिरिक्त सड़क प्रभार पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है। ऊपर बताये गए मद 2, 3 और 4 पर आने वाला व्यय 20/- रु० प्रति मी०टन से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्पादन शुल्क इसके अतिरिक्त देव होता है।

1 अक्टूबर, 1976 से 31 मार्च, 1977 की अवधि में सीमेंट पर देय मूल्य निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	मूल्य प्र०मी०टन	1-10-76 से 31-12-76 रुपये	1-1-77 से 26-1-77 रुपये	27-1-77 से 31-1-77 रुपये	1-2-77 से 31-3-77 रुपये
1.	गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूल्य	214.65	214.65	214.65	231.65
2.	पैकिंग प्रभार	40.94	40.95	40.95	40.95
3.	उत्पादन शुल्क	82.00	82.00	65.00	65.00
योग :		337.59	337.60	320.60	337.60

इससे यह पता चलेगा कि समय समय पर रेल भाड़े में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 27 जनवरी, 1977 से सीमेंट के उत्पादन शुल्क में 17 रु० प्रति मी० टन के हिसाब से कमी कर दी गई है। उक्त समायोजन उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिर बनाये रखने के विचार से किया गया था।

Census and Steps taken to bring the Sick and Closed Mills in working condition

1985. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have made any census of the existing industrial units in the village, rural, small scale and medium sectors;

(b) if so, how many of them are actually working, how many are on the sick list and how many have been closed down; and

(c) whether any steps are being taken to revive them and put them back in healthy working condition?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir. The Government conducted a Census of Small Scale Industries in 1973-74 with reference year 1972 for collection of data.

(b) Does not arise.

(c) For reviving sick units a Committee has been constituted in each State on which the State Director of Industries, Small Industries Service Institute, Nationalised banks, Financial Corporations and Associations of small scale industries are represented. The Committee examines the problems of sick and closed units and provides them integrated assistance to bring them back to health.

Constitution of Expert Committee on construction of Thermal Power Projects

1986. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have constituted Expert Committee to consider the possibility of reducing the construction time of the thermal power projects in the country;